

SHRI B. S. MURTHY : The N.D.M.C. borrows the services of engineers as and when they need them., therefore there was no possibility of asking the State Government that they would want an expert on such and such a subject and also a Scheduled Caste. Now the N.D.M.C. is thinking of forming its own cadres. As I have stated earlier, they wanted to have in a panel of 11 candidates for the three Assistant Engineers' posts and one has been reserved for a Scheduled Caste.

**TRANSFER OF CHANDNI CHOWK KOTWAL¹
DELHI TO GURDWARA SISGUNJ**

•473. SARDAR NARINDAR SINGH
BRAR

SARDAR GURCHARAN SINGH
TOHRA :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has recommended to the Union Government to hand over the part of the Chandni Chowk Kotwali, Delhi to the Sis Gunj Gurdwara free of cost keeping in view its sacred character and sentiments of the people;

(b) if so, whether Government propose to return the money already taken from the Gurdwara Sis Gunj Management; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b) No, Madam.

(c) The terms and conditions for the transfer of the Kotwali building to the Gurdwara Prabandhak Committee were mutually agreed upon between the Gurdwara Prabandhak Committee and the Delhi Administration.

सरदार नरिन्दर सिंह बरार : मैं मिनिसटर
साहब से पूछना चाहूंगा कि जब ईस्ट इंडिया
कम्पनी आई तो उसने भी आ कर यह कहा
कि सिखों की बेहद कुर्बानियों को मद्देनजर
रखते हुये यह जो कोतवाली है वह शीशगंज
का हिस्सा है तो उसके बाद क्या वजह है कि
हमारी अपनी हुकूमत ने इसको गुरुद्वारा का
हिस्सा नहीं माना जब कि सिखों की बेशुमार
कुर्बानियां हैं। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह,
मिस्टर झा, सबने यह कहा। इस पर भी इस
कोतवाली के लिये 16 लाख 35 हजार
रुपया लिया। उस वक्त भी इन लोगों ने यह
कहा कि गवर्नमेंट को यह मुफ्त देना चाहिये
और यह रुपया वापस कर देना चाहिये।

The question was actually asked on the Boor of the house by Sardar Narindar Singh Brar.

कोतवाली के लिये 16 लाख 35 हजार रुपया
लिया। उस वक्त भी इन लोगों ने यह कहा
कि गवर्नमेंट को यह मुफ्त देना चाहिये
और यह रुपया वापस कर देना चाहिये।

दुसरा सवाल यह है कि आप ने हर
जगह हर मन्दिर या मस्जिद के सामने पार्क
वगैरह बनाया है तो हमारे गुरुद्वारे के
सामने हमारे किसी गुरुद्वारे के सामने
हमारे को बनाने के लिये ऐसा कोई
नहीं आया - जो कोतवाली है उस को
गुरुद्वारे का हिस्सा मानते हैं हालांकि
हमारे लिये मिथोचोली अिकरी
रुपये देने को माना लेकिन उस के बाद
भी जब कि पार्क, स्राने वगैरह बनाने
के लिये और जगह एक रुपये के लिये
हैं तो उस जगह के लिये 35
हजार रुपये देने की क्या वजह है ?

†[सरदार नरेन्दर सिंह बरार : मैं मिनिसटर
साहब से पूछना चाहूंगा कि जब ईस्ट इंडिया
कम्पनी आई तो उसने भी आ कर यह कहा
कि सिखों की बेहद कुर्बानियों को मद्देनजर
रखते हुये यह जो कोतवाली है वह शीशगंज
का हिस्सा है तो उसके बाद क्या वजह है कि
हमारी अपनी हुकूमत ने इसको गुरुद्वारा का
हिस्सा नहीं माना जब कि सिखों की बेशुमार
कुर्बानियां हैं। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह,
मिस्टर झा, सबने यह कहा। इस पर भी इस
कोतवाली के लिये 16 लाख 35 हजार
रुपया लिया। उस वक्त भी इन लोगों ने यह
कहा कि गवर्नमेंट को यह मुफ्त देना चाहिये
और यह रुपया वापस कर देना चाहिये।

] Hindi translation.

दूसरा सवाल यह है कि आपने हर जगह, हर मन्दिर या मस्जिद के सामने, पार्क वगैरह बनाया है तो हमारे गुरुद्वारे के सामने, हमारे किसी गुरुद्वारे के सामने, इसको बनाने के लिये ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया। जो कोतवाली है उसको गुरुद्वारा का हिस्सा मानते हैं, हालांकि उसके लिये म्युचुअली एग्री किया और रुपया देने को माना, लेकिन इसके बाद भी जबकि पार्क, सराय, वगैरह बनाने के लिये और जगह एक रुपया गज पर देते हैं तो इस जगह के लिये 16 लाख 35 हजार रुपया लेने को क्या वजह थी ?]

सरदार नरिंदर सिंह ब्रार : میں نے تو

آپ سے یہی سوال کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کا پیسہ دیا تو یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے آخر کار اس کو گرانہ ہی ہے۔ پروبنڈھک کمیٹی نے مان لیا اس لئے کہ ہمارے پاس سانس لینے کو جگہ نہیں تھی۔ کوئی سوائے وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے ہم مجبور تھے آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے 16 لاکھ 35 ہزار روپیہ مانگا ہی تو میرا کہنا ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے سکھوں نے لئے خاص طور پر کیا فراخ دلی دکھلائی ہے جب کہ آپ کے سینڈھک منسٹر اور سب آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ مفت ملنی چاہئے۔

†[سرदार نرےندر सिंह ब्रार : मैंने तो आपसे यही सवाल किया है कि जो आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग का पैसा दिया तो यह जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, आखिरकार

SHRI B. S. MURTHY : As a matter of fact when this 0.7 acre was agreed to by the Prabandhak Committee, there was no question of selling the land. The Prabandhak Committee agreed to pay the cost of the superstructures worth about Rs. 16.35 lakhs and it also agreed that if the Government is able to get land free for the construction of Kotwali, there would be no question of charging any money for the land given but if they have to purchase, the Prabandhak Committee agreed to pay the cost.

उसको गिराना ही है, प्रबन्धक समिती ने मान लिया, इसलिये कि हमारे पास सांस लेने को जगह नहीं थी, कोई सराय वगैरह नहीं बना सकते थे, हम मजबूर थे, आपने नहीं दिया, आपने 16 लाख 35 हजार रुपया मांगा भी, तो मेरा कहना है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिखों के लिये खास तौर पर क्या फराखदिली दिखावाई है, जबकि आपके सीनियर मिनिस्टर और सब आदमी कह रहे हैं कि यह मुफ्त मिलनी चाहिये।]

SHRI B. S. MURTHY : The question does not arise as far as the Central Government is concerned. It is an agreement between the Delhi Administration and the Prabandhak Committee. The present estimated cost of the building is Rs.16.35 lakhs.

سرदार نریندر سنگھ بھار : میرے

سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ جب آپ کے سینڈھک منسٹر بھی یہ کہتے ہیں۔ ملبھوترا صاحب اور جھا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مفت دینا چاہئے تو آپ نے کوئی وچار کیا اور اگر نہیں کیا تو کیا وجہ ہے؟ میں نے یہ پوچھا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔

†[सरदार नरेंदर सिंह ब्रार : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो यह कहा है कि जब आपके सीनियर मिनिस्टर भी कहते हैं, मल्होत्रा साहब और झा साहब भी कहते हैं कि इसको मुफ्त देना चाहिये तो आपने इस पर कोई विचार किया और अगर नहीं किया तो क्या वजह है? मैंने यह पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया।]

SHRI B. S. MURTHY : I am not able to understand it.

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : I can repeat it.

श्री के० के० शाह : मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि फ्लोट में देने में क्या हर्ज है। यह आपका सवाल है। तो दिल्ली

एहमिनिस्ट्रेशन ने प्रबन्धक कमेटी के साथ समझौता किया। आज तक कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि खड़े हुये मकान को गिरा दें अगर उस जगह पर किसी के बारे में कोई मेमोरियल करना हो, फिर भी यह मंजूर किया गया कि मकान की कीमत हम दे देते हैं कलेक्शन कर के। तो यह एग्रीमेंट हुआ कि अच्छा हो कोतवाली का मकान आप दे दें, दूसरी जगह कोतवाली बना देंगे। प्रबन्धक कमेटी जिसमें हमारे अकाली दोस्त मेजारिटी में हैं इनके साथ समझौता हुआ तो फिर आप क्यों परेशान हैं।

سردار نریندر سنگھ برار : میں

پریشان نہیں ہوں - میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا - لکھیر - میں نے یہ سوال نہیں کیا - میں تو یہ کہتا ہوں کہ سردار سورن سنگھ صاحب نے یہ کہا کہ ان کو مفت دینا چاہئے آپ کے سینئر منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں - تو اس کے بارے میں آپ نے کیا وچار کیا - یہ میرا سوال ہے -

†[सरदार नरेंद्र सिंह भार : मैं परेशान नहीं हूँ। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। लुक हीयर, मैंने यह सवाल नहीं किया। मैं तो यह कहता हूँ कि सरदार स्वर्ण सिंह, शा साहब, सबने यह कहा कि उनको मुफ्त देना चाहिये। आपके सीनियर मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं। तो उसके बारे में आपने क्या विचार किया? यह मेरा सवाल है।]

श्री के० के० शाह : आपस आपस में हुआ समझौता किसी की ओपीनियन से ज्यादा महत्व का है, ऐसा मैं मानता हूँ।

डा० भाई महावीर : महोदया, इस समझौते की बात कही गई है, यह ठीक है कि समझौता हुआ और उसके अन्तर्गत साढ़े सोलह लाख रुपया सरकार को प्रबन्धक कमेटी की तरफ से दिया गया है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आज से

सात-आठ महीने पहले दिल्ली की एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने इस बात का प्रस्ताव किया कि जितना रुपया लिया गया है वह रुपया वहाँ पर एक नेशनल मेमोरियल बनाने के लिये सरकार कांट्रीब्यूशन के तौर पर दे दे, समझौते की जो धारायें हैं उनका सम्मान रहे परन्तु जैसे कि गालिब मेमोरियल के लिये 16 लाख रुपया दिया गया वैसे दे दें, अब गालिब का जो स्थान है वह हम जानते हैं, गालिब ने जो कुछ किया है, राष्ट्र के संघर्ष में जो कुछ गालिब की देन है, उसको अलग रखिये, परन्तु इस स्थान का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और उस महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार अगर 16 लाख रुपया गालिब के लिये दे सकती है तो इसके लिये भी दे सकती है कि केन्द्र के लिये राष्ट्रीय स्फूर्ति का एक स्मारक खड़ा हो सके। तो जो प्रस्ताव एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने किया था क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और अगर किया है तो क्या फैसला किया है और अगर उसको अस्वीकार किया है तो क्यों किया है ?

श्री के० के० शाह : 11 फरवरी के रोज ऐसा प्रस्ताव पास हुआ ऐसी हमें खबर मिली लेकिन आज तक वह प्रस्ताव मेरे यहाँ नहीं पहुँचा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में शायद भेजना होगा ऐसा सोच कर के नहीं भेजा होगा, लेकिन मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी तलाश किया, कोई पक्की तो नहीं लेकिन ओरल इन्फार्मेशन मिली है, आई स्टैंड करेक्टेड कि अभी तक यहाँ पर भी नहीं पहुँचा है और जब पहुँचेगा तो इस पर जरूर सोचा जायेगा।

डा० भाई महावीर : मैं यह जानना चाहता हूँ ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No more.

डा० भाई महावीर : वह प्रस्ताव जो आपके पास आये तो उस पर आप विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री लोकनाथ मिश्र : वह तो उन्होंने कहा ॥

†[] Hindi transliteration.